@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

'जहां बीमार वहां उपचार': नरेन्द्र मोदी

वर्ष-16, अंक-11 01-15 जून, 2021 (पाक्षिक) ₹20

'कोविड की दूसरी लहर के विरुद्ध हमारी लड़ाई हर एक की जान बचाने की है'

नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा के 'सेवा ही संगठन 2.0' अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए कोविड राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

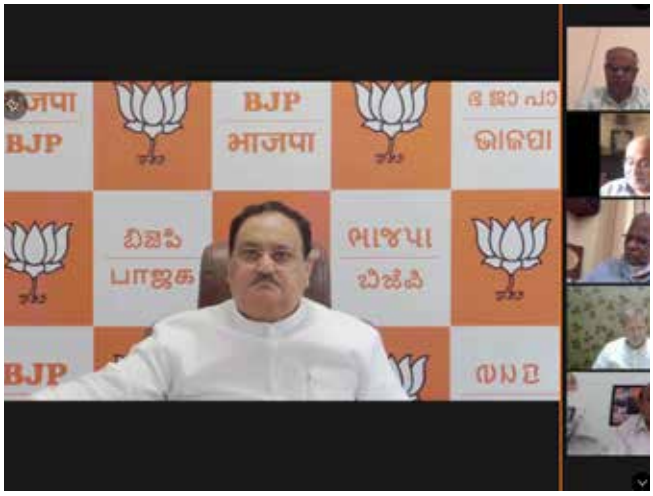

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के भाजपा प्रदेश अध्यक्षों, प्रभारियों, पदाधिकारियों और सांसदों को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्षों, संगठन सचिवों, प्रभारियों, सह-प्रभारियों और सांसदों को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात यास से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु तैयारियों की समीक्षा करते केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली में कोविड-19 रोधी दवा 2-डीजी की पहली खेप जारी करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 हर एक जीवन बचाने की है हमारी लड़ाई: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 18 मई को विभिन्न राज्यों और जिलों के फील्ड स्तर के अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी से निपटने में उनके अनुभवों के बारे में बातचीत की...

08 'देश की सभी तहसीलों और जिलों में टेलीमेडिसिन सेवा का विस्तार होना जरूरी'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड से जुड़ी...

09 'जहां बीमार वहां उपचार'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 21 मई को वाराणसी के डॉक्टरों और अधिकारियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान...

14 प्रधानमंत्री ने गुजरात में चक्रवात 'तौकते' प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवात 'तौकते' के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति...

27 पीएम-किसान योजना से पहली बार पश्चिम बंगाल के किसान होंगे लाभान्वित: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 मई को...

वैचारिकी

राष्ट्र का अर्थ/ दीनदयाल उपाध्याय 24

श्रद्धांजलि

नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता 26

लेख

मोदीजी ने भारत को विश्व शक्ति बनाया/ रघुवर दास 28

अन्य

हाई पॉजिटिविटी रेट वाले क्षेत्रों में जांच को और बढ़ाने की जरूरत: नरेन्द्र मोदी 11

पीएम केयर्स के माध्यम से खरीदे जाएंगे 1.5 लाख ऑक्सीकेयर सिस्टम 13

एसीसी बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने हेतु 18,100 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम को मिली मंजूरी 15

असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्वा सरमा 16

एन रंगासामी ने ली पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ 18

भारत में आया 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का सर्वाधिक एफडीआई 19

डीएपी खाद पर बढ़ाई गई 140 प्रतिशत सब्सिडी 20

जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को 1,605 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान जारी 21

डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड-19 रोधी दवा 2-डीजी जारी 22

'कोविड-19 के बाद धरती अब पहले जैसी नहीं रहेगी' 32

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की प्रगति का जायजा लिया, यह एक ऐसा प्रयास है जो भविष्य में हमारे नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करेगा और 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा देगा।

अमित शाह

सभी प्रौद्योगिकीविदों और वैज्ञानिकों को 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' की बधाई। यह दिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसने भारत को दुनिया भर में एक नई ताकत और उपस्थिति दी। राष्ट्र गर्व से हमारे अभिनव विचारों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को याद करता है।

बी.एल. संतोष

स्पुतनिक वी निर्माताओं की ओर से अच्छी खबर आ रही है। आरडीआईएफ, रूस और पैनेसिया बायोटेक ने भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। जहां कुछ लोग भारत को नीचा दिखाने के लिए टूलकिट बनाते हैं, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार वैक्सीन उत्पादन में तेजी ला रही है। #IndiaFightsBack

जगत प्रकाश नड्डा

पहली बार बंगाल के लाखों किसान भाइयों को इस योजना का लाभ मिलना शुरु हो गया है। इतने वर्षों तक किसानों को इस लाभ से वंचित रखा गया। हमने इस विषय को जोरदार तरीके से रखा था। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ अब वहां के किसानों को मिलने लगा है, ये बहुत संतोष का विषय है।

राजनाथ सिंह

पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के दस करोड़ किसानों को आठवीं किस्त प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जारी की है। कोरोना संकट के दौरान किसानों को पीएम किसान निधि से बहुत राहत मिली है। आज (14 मई) से बंगाल के किसान भी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद!

नितिन गडकरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सात साल पूरे कर लिए हैं। इन सात सालों में देश में देश ने अभूतपूर्व विकास और सुधारों का दौर देखा है, जो अब भी जारी है। सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां जन-जन तक पहुंची है। पिछले सात सालों में देश ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिजली, स्वच्छता से लेकर अन्यान्य क्षेत्रों में तेज़ विकास देखा है। गरीब, किसान और वंचित के सशक्तिकरण का हर संभव प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय एकता की भावना कोविड 19 महामारी को हराएगी

पूरा राष्ट्र कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का अदम्य साहस एवं दृढ़ संकल्पशक्ति के साथ सामना कर रहा है। सारा देश इस वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त करने की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ एकजुट है तथा लोग एक-दूसरे की सहायता कर अद्भुत एकता का परिचय दे रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी निरंतर विभिन्न व्यक्तियों एवं समूह से संवाद कर महामारी से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने में लगे हुए हैं। प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कई चरणों में संवाद के अलावा उन्होंने देश के प्रख्यात चिकित्सकों के समूह, दवा एवं वैक्सीन निर्माताओं से संवाद करते हुए अनेक उच्चस्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की है, जिससे देशभर में राहत कार्य तेज हुआ है। जहां पूरा देश आज एकजुट है, वहीं इसका परिणाम महामारी के घटते प्रभाव के रूप में दिखने लगा है और इसमें अब कोई संदेह नहीं दिखता कि बहुत ही कम समय में इसे नियंत्रित कर लिया जाएगा।

मोदी सरकार ने ऑक्सीजन, आवश्यक चिकित्सीय उपकरण एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, साथ ही 80 करोड़ जनता को महामारी के दौरान निःशुल्क राशन की व्यवस्था भी की है। इस दौरान विदेश तथा विभिन्न संगठनों से प्राप्त 17,755 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 15,961 ऑक्सीजन सिलिंडर, 19 ऑक्सीजन प्लांट तथा 12,913 वेंटिलेटर को भी केन्द्र सरकार ने कई राज्यों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया है। साथ ही 1.5 लाख ऑक्सीकेयर इकाई को भी पीएम केयर के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। इसके अलावा 21.80 करोड़ टीके भी प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए हैं ताकि विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की गति और भी अधिक तेज हो सके। इन सबका परिणाम अब देश में ऑक्सीजन, आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण एवं दवाइयां तथा टीकों की उपलब्धता के रूप में देखा जा सकता है।

सारा देश कोविड-19 महामारी पर विजय प्राप्त करने की दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ एकजुट है तथा लोग एक-दूसरे की सहायता कर अद्भुत एकता का परिचय दे रहे हैं

विभिन्न प्रदेशों द्वारा लगाए गए 'लॉकडाउन' के कारण जन-जीवन जहां एक ओर धीमा पड़ा है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक महामारी के दौर में भी देश के किसानों ने अपनी अनुपम उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ाया है। वर्ष 2020-21 में भारत ने रिकार्ड 2 करोड़ टन चावल का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष 1.77 करोड़ टन था। ध्यान रहे कि पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी में यह निर्यात 0.85 करोड़ टन से दुगुना हो गया था। ये सभी उपलब्धियां मोदी सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का ही परिणाम हैं, फलस्वरूप किसान आज उत्साह एवं ऊर्जा से भरे हुए हैं। पीएम-किसान के अंतर्गत हाल ही में 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 20 हजार करोड़ रुपए के सीधे हस्तांतरण से किसानों के लिए नकद उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। महामारी के दौरान भी गेहूं एवं धान की रिकार्ड खरीदी से जहां एक ओर किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुणा अधिक दाम सुनिश्चित किया गया है, वहीं दूसरी ओर किसानों के खाते में सीधे भुगतान की व्यवस्था कर बिचौलियों का खेल खत्म किया गया है। डीएपी में सब्सिडी की ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर किसानों के और अधिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

एक ओर जहां पूरा देश महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए एकजुट है, वहीं दूसरी ओर देश के चिकित्सक, नर्स, चिकित्सकीय सहयोगी, लैब तकनीशियन, प्रशासनिक अधिकारियों एवं कोरोना योद्धाओं ने अपने आप को खतरे में डालकर जिस प्रकार लोगों की सेवा की है, उससे देश का गौरव बढ़ा है। देश के औद्योगिक क्षेत्र, दवा एवं वैक्सीन निर्माताओं ने महामारी के कठिन दौर में ऑक्सीजन, दवा एवं वैक्सीन की उपलब्धता के लिए जिस प्रकार से युद्ध-स्तर पर अपने संसाधनों को जुटाया, वह वास्तव में अभिनंदनीय है। परन्तु यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का एक वर्ग अपने निहित राजनैतिक स्वार्थ के लिए देश में संदेह एवं आशंका का वातावरण बनाना चाहा। यह समय था जब कांग्रेस देश के साथ खड़ी होती तथा लोगों के दुःख-दर्द बांटती, परंतु उसने इस राष्ट्रीय त्रासदी के समय अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने का कुप्रयास किया। भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है, जिन्होंने पूरे देश में 'सेवा ही संगठन-2' के माध्यम से लोगों की सेवा की एवं जन-जन को राहत पहुंचाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि एकजुट भारत कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

प्रधानमंत्री की कोविड-19 के बारे में राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बातचीत

हर एक जीवन बचाने की है हमारी लड़ाई: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 18 मई को विभिन्न राज्यों और जिलों के फील्ड स्तर के अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी से निपटने में उनके अनुभवों के बारे में बातचीत की।

बातचीत के दौरान अधिकारियों ने कोविड की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और प्रधानमंत्री को हाल के संक्रमण के मामलों में आए उछाल से निपटने के क्रम में उठाये गये अभिनव कदमों से अवगत कराया।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा से संबंधित बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण को उन्नत करने की दिशा में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बारे में भी बताया। श्री मोदी ने अधिकारियों से सर्वोत्तम उपायों और अभिनव कदमों को संकलित करने को कहा ताकि उनका उपयोग देश के अन्य जिलों में किया जा सके।

बातचीत के बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस कठिन समय में देश के स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कामगारों और प्रशासकों द्वारा दिखाए गए समर्पण एवं दृढ़ता की सराहना की और उनसे आगे भी इसी जोश के साथ काम करते रहने का आग्रह किया।

श्री मोदी ने कहा कि देश का हर जिला एक दूसरे से अलग है और उनकी अपनी अनूठी चुनौतियां हैं। उन्होंने जिले के अधिकारियों से कहा कि आप अपने जिले की चुनौतियों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए जब आपका जिला जीतता है, तो देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है, तो देश कोरोना को हराता है।

श्री मोदी ने उन अधिकारियों की सराहना की जो कोविड-19 से संक्रमित होने के बावजूद बिना छुट्टी लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी कई लोगों के लिए प्रेरणा हैं और उनके द्वारा किए गए त्याग को वो समझते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सभी अधिकारियों की इस लड़ाई के फील्ड कमांडर की तरह बेहद अहम भूमिका है। उन्होंने टिप्पणी की कि स्थानीय कन्टेनमेंट जोन, सक्रिय जांच और लोगों को सही एवं पूरी जानकारी इस वायरस के खिलाफ हथियार हैं। इस समय कुछ राज्यों में जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या घट रही है, वहीं कई अन्य राज्यों में यह संख्या बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने घटते संक्रमण की पृष्ठभूमि में और अधिक सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया।

ग्रामीण और दुर्गम इलाकों की ओर होना चाहिए हमारा ध्यान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा कि लड़ाई हर एक जीवन को बचाने की है और हमारा ध्यान ग्रामीण और दुर्गम इलाकों की ओर होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से ग्रामीण आबादी के लिए राहत सामग्री को आसानी से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

श्री मोदी ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे अपने जिले के प्रत्येक नागरिक के जीवन को आसान बनाने पर ध्यान दें। उन्होंने संक्रमण को रोकने और साथ ही आवश्यक सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने बताया कि पीएम केयर्स फंड के जरिए देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है और कई अस्पतालों में इन संयंत्रों ने काम करना शुरू भी कर दिया है।

श्री मोदी ने बीमारी की गंभीरता को कम करने और अस्पताल में भर्ती एवं मृत्यु दर में कमी लाने में टीकाकरण के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लगातार बड़े पैमाने पर कोरोना के टीकों की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय टीकाकरण की प्रणाली और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रहा है। राज्यों को अगले 15 दिनों का कार्यक्रम पहले से देने का प्रयास किया जा रहा है। श्री मोदी ने टीकों की बर्बादी रोकने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि बिस्तरों और टीकों की उपलब्धता की जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों को अधिक सुविधा हो जाती है। इसी तरह कालाबाजारी पर रोक लगनी चाहिए और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अग्रिम पंक्ति के कामगारों का मनोबल ऊंचा रखते हुए उन्हें संगठित करना चाहिए।

श्री मोदी ने गांव के लोगों द्वारा अपने खेतों में सामाजिक दूरी बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि गांव के लोग जानकारी को समझकर उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। यही गांव के लोगों की ताकत है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वायरस के खिलाफ सर्वोत्तम उपायों को अपनाना चाहिए। श्री मोदी ने लोगों से कहा कि आप इस दिशा में कुछ नया करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप इसके लिए नीति में बदलाव के बारे में सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने लोगों से कोविड के मामलों में कमी आने के बावजूद सतर्क रहने की अपील की। ■

'देश की सभी तहसीलों और जिलों में टेलीमेडिसिन सेवा का विस्तार होना जरूरी'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड से जुड़ी स्थितियों पर चर्चा करने के लिए देशभर के डॉक्टरों के एक समूह के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने चिकित्सा वर्ग और पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड की दूसरी लहर की असाधारण परिस्थितियों के खिलाफ दिखाए गए अनुकरणीय संघर्ष के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि पूरा देश उनका ऋणी है।

उन्होंने कहा कि चाहे परीक्षण हो, दवाओं की आपूर्ति करना हो या रिकॉर्ड समय में नए बुनियादी ढांचे की स्थापना हो, यह सब कुछ तेज गति से किया जा रहा है। ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति में आने वाली कई चुनौतियों को दूर किया जा रहा है। देश की ओर से मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों, जैसे कोविड उपचार में एमबीबीएस छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करना, ने स्वास्थ्य प्रणाली को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई है।

श्री मोदी ने रेखांकित किया कि टीकाकरण कार्यक्रम को अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं (फ्रंटलाइन वॉरियर्स) के साथ शुरू करने की रणनीति ने दूसरी लहर में काफी लाभ दिया है। देश में लगभग 90% स्वास्थ्य पेशेवरों को पहले ही टीके की पहली खुराक लग चुकी है। टीकों ने अधिकांश डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से ऑक्सीजन ऑडिट को अपने दैनिक प्रयासों में शामिल करने का आग्रह किया। यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में मरीजों का 'घर पर एकांतवास में रहकर' (होम आइसोलेशन) इलाज हो रहा है, उन्होंने डॉक्टरों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि मरीज की घर में होने वाली देखभाल एसओपी के आधार पर संचालित हो।

श्री मोदी ने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन ने बड़ी भूमिका निभाई है और इस सेवा का ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार करने की जरूरत है। उन्होंने उन डॉक्टरों की सराहना की, जो टीम बना रहे हैं और गांवों में टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध करा रहे हैं।

श्री मोदी ने सभी राज्यों के डॉक्टरों से ऐसी टीम बनाने, एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्रों और एमबीबीएस इंटर्न को प्रशिक्षित करने और देश की सभी तहसीलों व जिलों में टेलीमेडिसिन सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने की अपील की।

शारीरिक देखभाल के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक देखभाल जरूरी

प्रधानमंत्री ने म्यूकोरमिकोसिस की चुनौती पर भी चर्चा की और कहा कि डॉक्टरों को सक्रिय कदम उठाने और इस बारे में जागरूकता लाने के अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत हो सकती है। उन्होंने शारीरिक देखभाल के महत्व के साथ मनोवैज्ञानिक देखभाल के महत्व को भी रेखांकित किया।

बातचीत के दौरान डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री को हाल के दिनों में मामलों में उछाल के दौरान उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। डॉक्टरों ने टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता देने के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार जताया।

डॉक्टरों ने अपने अनुभव, काम करने के सर्वोत्तम तरीकों और नए-नए प्रयासों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में गैर-कोविड मरीजों की उचित देखभाल करने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ■

प्रधानमंत्री की वाराणसी के डॉक्टरों और अधिकारियों से बातचीत

'जहां बीमार वहां उपचार'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 21 मई को वाराणसी के डॉक्टरों और अधिकारियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान वाराणसी के डॉक्टरों और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के निरंतर और सक्रिय नेतृत्व के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जिससे स्वास्थ्य संरचना बढ़ाने और आवश्यक दवाओं तथा वेंटिलेटर तथा ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिली।

कोविड को नियंत्रित करने के लिए पिछले एक महीने में किए गए प्रयासों, टीकाकरण की स्थिति तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। डॉक्टरों ने श्री मोदी को यह भी बताया कि वे म्यूरोर्मिकोसिस के खतरे को लेकर सचेत हैं और उनके द्वारा कदम उठाए गए हैं तथा रोग प्रबंधन के लिए सुविधाएं तैयार की गई हैं। श्री मोदी ने कोविड से लड़ने वाली मानव शक्ति के निरंतर प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया और अधिकारियों तथा डॉक्टरों को प्रशिक्षण सत्र, वेबीनार आयोजित करने की सलाह दी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे चिकित्सा सहायकों और डॉक्टरों के लिए। उन्होंने अधिकारियों से जिले में टीके की बर्बादी को कम करने की दिशा में काम करने को कहा।

श्री मोदी ने काशी के डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों, वार्ड ब्वाय, एंबुलेंस चालकों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मचारियों के कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बनारस में कम समय में तेजी से ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने और बहुत कम समय में पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल को सक्रिय करने की सराहना की।

श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि वाराणसी में एकीकृत कोविड कमान प्रणाली ने बहुत अच्छा काम किया और कहा कि वाराणसी का उदाहरण दुनिया को प्रेरित करता है। उन्होंने महामारी को काफी हद तक नियंत्रित करने में मेडिकल टीम के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके लंबी लड़ाई लड़ने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जो योजनाएं बनीं हैं और जो अभियान चलाए गए हैं उनसे कोरोना से लड़ने में काफी मदद मिली है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए शौचालय, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज की सुविधा, उज्ज्वला योजना के तहत गैस

सिलेंडर, जन धन बैंक खाता या फिट इंडिया अभियान, योग और आयुष के प्रति जागरूकता जैसे कदमों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की शक्ति में वृद्धि हुई है।

श्री मोदी ने कोविड प्रबंधन में नया मंत्र 'जहां बीमार वहां उपचार' दिया। उन्होंने कहा कि मरीज के दरवाजे पर उपचार उपलब्ध कराने से स्वास्थ्य प्रणाली पर भार कम होगा। प्रधानमंत्री ने माइक्रो-कंटेनमेंट जोन पहल की प्रशंसा तथा दवाओं की होम डिलीवरी की सराहना की।

पिछले कुछ वर्षों में बनाई गई योजनाएं और चलाए गए अभियानों से कोरोना से लड़ने में काफी मदद मिली है

'काशी कवच' टेली मेडिसिन सुविधा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वास्थ्य कर्मचारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को जहां तक संभव हो सके वहां तक व्यापक बनाने का अनुरोध किया। श्री मोदी ने कहा कि 'काशी कवच' नामक टेली मेडिसिन सुविधा प्रदान करने में डॉक्टरों, लैब तथा ई-मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ लाने का कदम बहुत नवाचारी है।

श्री मोदी ने गांवों में कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में आशा तथा एएनएम कर्मियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया और स्वास्थ्य अधिकारियों से उनकी क्षमताओं और अनुभवों का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस दूसरी लहर के दौरान अग्रणी कर्मचारी लोगों की सेवा सुरक्षित ढंग से करने में सक्षम हुए हैं क्योंकि उन्हें टीका लगाया गया था। उन्होंने सभी से अपनी बारी आने पर टीका लगाने का आग्रह किया।

श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों के कारण पूर्वांचल में बच्चों में इनसेफ्लाइटिस मामलों में काफी हद तक नियंत्रण किए जाने का उदाहरण दिया। उन्होंने महामारी के खिलाफ लड़ाई में ब्लैक फंगस द्वारा पेश नई चुनौती से सचेत रहने को कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व चेतावनियों और इससे निपटने के लिए आवश्यक तैयारियों के प्रति ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

श्री मोदी ने कोविड के विरुद्ध लड़ाई में वाराणसी के जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से लोगों से जुड़े रहने का आग्रह किया और सलाह दी कि वे आलोचनाओं के बावजूद अपनी चिंताओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील रहें। उन्होंने कहा कि यदि किसी नागरिक को किसी भी तरह की शिकायत है तो इसकी चिंता करना जन प्रतिनिधियों का दायित्व है। श्री मोदी ने शहर की स्वच्छता बनाए रखने का वादा निभाने के लिए वाराणसी के लोगों की प्रशंसा की। ■

डीआरडीओ ने कोविड-19 एंटीबॉडी पहचान किट विकसित की

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एण्ड एलायड सांसेज (डीआईपीएएस) ने सीरो-निगरानी के लिए एंटीबॉडी पहचान आधारित किट 'डिपकोवैन', डीपास-वीडीएक्स कोविड-19 IgG एंटीबॉडी माइक्रोवेल एलिसा विकसित की है।

रक्षा मंत्रालय की 21 मई को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार डिपकोवैन किट 97 प्रतिशत उच्च संवेदनशीलता और 99 प्रतिशत विशिष्टता के साथ सार्स सीओवी-2 वायरस के स्पाइक के साथ-साथ न्यूक्लियोकैप्सिड (एस एंड एन) प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है। किट नई दिल्ली की कंपनी वैनगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित की गई।

डिपकोवैन किट स्वदेश में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई और बाद में दिल्ली में निर्दिष्ट अस्पतालों में 1,000 से अधिक मरीज नमूनों पर इसका व्यापक सत्यापन किया गया। उत्पाद के तीन बैचों पर सत्यापन का काम पिछले एक वर्ष के दौरान किया गया। इस किट को अप्रैल, 2021 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा मंजूरी दी गई।

इस उत्पाद को बिक्री और वितरण के लिए बनाने की नियामक मंजूरी मई, 2021 में भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई।

हाई पॉजिटिविटी रेट वाले क्षेत्रों में जांच को और बढ़ाने की जरूरत: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड और टीकाकरण से जुड़ी स्थिति पर चर्चा के लिए 15 मई को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को देश में कोविड से संबंधित मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी।

श्री मोदी को बताया गया कि देश में जांच की संख्या तेजी से बढ़ी है, मार्च की शुरुआत में प्रति हफ्ते कोविड-19 के लिए लगभग 50 लाख जांच की जा रही थी जो अब बढ़कर प्रति हफ्ते लगभग 1.3 करोड़ हो गयी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को जांच में धीरे-धीरे घट रही पॉजिटिविटी रेट और बीमारी से उबरने की बढ़ती दर की भी जानकारी दी।

यह चर्चा की गयी कि हर दिन सामने आ रहे चार लाख से अधिक मामले स्वास्थ्यकर्मियों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप अब कम हो रहे हैं। अधिकारियों ने कोविड की राज्य और जिला स्तर की स्थिति, जांच, ऑक्सीजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, टीकाकरण रोडमैप पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

कोविड-19 जांच की संख्या मार्च की शुरुआत में प्रति हफ्ते के लगभग 50 लाख से बढ़कर अब प्रति हफ्ते लगभग 1.3 करोड़ हो गयी है

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विशेष रूप से उन राज्यों के लिए स्थानीयकृत नियंत्रण रणनीति समय की जरूरत है जहां जिलों में जांच पॉजिटिविटी रेट (टीपीआर) अधिक है। उन्होंने निर्देश दिया कि आरटी पीसीआर और रैपिड टेस्ट दोनों के उपयोग के साथ, विशेष रूप से उच्च जांच पॉजिटिविटी रेट वाले क्षेत्रों में जांच को और बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को अपने प्रयासों का सही नतीजा न मिलने पर दिखने वाली बड़ी संख्या का दवाब न लेते हुए पारदर्शी तरीके से अपनी संख्या की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने घर-घर जाकर जांच और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने सभी आवश्यक साधनों के साथ आशा और आंगनवाड़ी

कर्मचारियों को सशक्त बनाने के बारे में भी बात की। श्री मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन और इलाज के लिए दिशानिर्देश चित्रों के साथ-साथ आसान भाषा में उपलब्ध कराने को कहा।

श्री मोदी ने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक वितरण योजना तैयार की जाए, जिसमें ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसे उपकरणों के संचालन के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को जरूरी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और ऐसे चिकित्सा उपकरणों के सुचारू संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। श्री मोदी ने कुछ राज्यों में वेंटिलेटर के स्टोरेज में पड़े होने की कुछ रिपोर्टों को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वेंटिलेटर के उपयोग और संचालन का तत्काल ऑडिट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरी हो तो स्वास्थ्यकर्मियों को वेंटिलेटर के ठीक से संचालन के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रदान की जानी चाहिए।

श्री मोदी ने कहा कि कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई का वैज्ञानिक और विषय के विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन किया है और यह जारी रहेगा।

अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को टीकाकरण प्रक्रिया और 45 साल से ज्यादा उम्र की आबादी को राज्यवार तरीके से दिए गए टीके के बारे में जानकारी दी। भविष्य में टीके की उपलब्धता के रोडमैप पर भी चर्चा की गयी। ■

रेमडेसिविर समेत सभी दवाओं के उत्पादन में भारी वृद्धि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई को एक उच्चस्तरीय बैठक कर ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता व आपूर्ति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को बताया गया कि सरकार कोविड प्रबंधन और म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की आपूर्ति की निगरानी कर रही है।

श्री मोदी को ऐसी हर दवा के लिए एपीआई के मौजूदा उत्पादन और स्टॉक के बारे में भी बताया गया। इस पर चर्चा की गई कि राज्यों को काफी मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि पिछले कुछ हफ्तों में रेमडेसिविर समेत सभी दवाओं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत का फार्मा सेक्टर काफी सशक्त है और सरकार का उसके साथ लगातार करीबी समन्वय सभी दवाओं की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति का भी जायजा लिया।

इस पर भी चर्चा हुई कि कोरोना की पहली लहर में पीक के दौरान हुई ऑक्सीजन की आपूर्ति से अब तीन गुना ज्यादा आपूर्ति हो रही है। श्री मोदी को ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर भारतीय वायुसेना के विमानों और ऑक्सीजन रेल के संचालन के बारे में जानकारी दी गई।

श्री मोदी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडरों की खरीद की स्थिति के साथ-साथ देशभर में लगाए जा रहे पीएसए संयंत्रों की स्थिति के बारे में भी बताया गया।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्यों को समयबद्ध तरीके से वेंटिलेटरों का संचालन करने के लिए कहा जाना चाहिए और निर्माताओं की मदद से तकनीकी और प्रशिक्षण संबंधी मसलों को हल किया जाए। ■

लगातार पांच दिनों में दैनिक 20 लाख से अधिक हुईं कोविड जांचें

भारत ने पिछले 24 घंटों में (23 मई की सुबह तक) 21.23 लाख से अधिक जांचों के साथ सबसे अधिक जांच करने का एक बार फिर नया कीर्तिमान बनाया है। लगातार पांच दिनों में दैनिक 20 लाख से अधिक जांचें भी की गईं। भारत ने जांच करने की अपनी क्षमता जनवरी, 2020 की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर अब 25 लाख जांच प्रतिदिन कर ली है। पिछले 24 घंटों में कुल मिलाकर देश में 21,23,782 जांचें की गईं। दैनिक पॉजिटिविटी दर कम होकर 11.34 प्रतिशत पर आ गई।

एक अन्य सकारात्मक घटनाक्रम में भारत ने अब लगातार सातवें दिन तीन लाख से कम दैनिक नए मामले दर्ज कराये। पिछले 24 घंटों में 2,40,842 दैनिक नए मामले दर्ज कराये गए। 17 अप्रैल, 2021 के बाद से यह सबसे कम संख्या है, जब दैनिक नए मामले 2.34 लाख थे। भारत की दैनिक रिकवरी लगातार नौवें दिन दैनिक नए

मामलों की तुलना में अधिक रही। पिछले 24 घंटों में 3,55,102 रिकवरी दर्ज की गई। भारत की कुल रिकवरी अब 2,34,25,467 हो गई है। राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 88.30 प्रतिशत हो गई।

दूसरी तरफ, भारत के कुल सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर 23 मई को 28,05,399 पर आ गई। पिछले 24 घंटों में 1,18,001 की शुद्ध गिरावट दर्ज की गई। अब यह देश के कुल पॉजिटिव मामलों की 10.57 प्रतिशत है। राष्ट्रीय मृत्यु दर वर्तमान में 1.13 प्रतिशत है। ■

पीएम केयर्स के माध्यम से खरीदे जाएंगे 1.5 लाख ऑक्सीकेयर सिस्टम

पीएम-केयर्स फंड से 322.5 करोड़ रुपये की लागत से 1,50,000 ऑक्सीकेयर सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई है। यह मरीजों के एसपीओ2 स्तरों के आंके गए माप के आधार पर उन्हें दी जा रही ऑक्सीजन को नियंत्रित रखने के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई एक व्यापक प्रणाली है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 12 मई को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस सिस्टम को दो विन्यास में विकसित किया गया है। इसके मूल वर्जन में 10 लीटर वाला ऑक्सीजन सिलेंडर, एक प्रेशर रेगुलेटर-सह-फ्लो कंट्रोलर, एक ह्यूमिडिफायर और नाक के लिए एक लघुनलिका होती है। ऑक्सीजन के प्रवाह को मैनुअल रूप से एसपीओ2 की रीडिंग के आधार पर नियंत्रित या समायोजित किया जाता है। इसके इंटेलिजेंट विन्यास में मूल वर्जन के अलावा एक लो प्रेशर रेगुलेटर के जरिए ऑक्सीजन के स्वतः नियंत्रण या समायोजन के लिए एक प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल प्रणाली और एक एसपीओ2 प्रोब शामिल हैं।

ऑक्सीकेयर सिस्टम नियमित माप और ऑक्सीजन प्रवाह के मैनुअल समायोजन की आवश्यकता को समाप्त कर स्वास्थ्यकर्मियों के काम के बोझ और जोखिम को कम करता है

एसपीओ2 आधारित ऑक्सीजन नियंत्रण प्रणाली दरअसल मरीज के एसपीओ2 स्तर के आधार पर ऑक्सीजन की खपत का अनुकूलन करती है और प्रभावकारी रूप से पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर के उपयोग की निरंतरता को बढ़ा देती है।

सिस्टम से प्रवाह शुरू करने के लिए एसपीओ2 की आरंभिक सीमा वाले माप या मान को स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा समायोजित किया जा सकता है और सिस्टम द्वारा एसपीओ2 के स्तर की निरंतर निगरानी करने के साथ-साथ इसे दर्शाया भी जाता है।

ऑक्सीकेयर सिस्टम नियमित माप और ऑक्सीजन प्रवाह के मैनुअल समायोजन की आवश्यकता को समाप्त कर स्वास्थ्यकर्मियों के काम के बोझ और जोखिम को कम करता है। इस तरह से यह टेली-परामर्श की भी सुविधाजनक बना देता है।

यह स्वचालित सिस्टम इसके साथ ही किसी भी तरह की भारी कमी होने की स्थितियों जैसे कि एसपीओ2 का माप या मान कम होने और प्रोब के डिस्कनेक्ट होने पर उपयुक्त ऑडियो चेतावनी भी देता है। इन ऑक्सीकेयर सिस्टम का उपयोग घरों, क्वारंटाइन केंद्रों, कोविड केयर केंद्रों और अस्पतालों में किया जा सकता है।

इसके अलावा, ऑक्सीजन का ज्यादा प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नॉन-रिब्रीथर मास्क (एनआरएम) को ऑक्सीकेयर सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप 30-40% ऑक्सीजन की बचत संभव हो जाती है।

डीआरडीओ ने भारत में कई कंपनियों को यह तकनीक हस्तांतरित की है जो पूरे भारत में सभी के उपयोग के लिए ऑक्सीकेयर सिस्टम तैयार करेंगी।

वर्तमान चिकित्सा प्रोटोकॉल में समस्त गंभीर और अति गंभीर कोविड-19 मरीजों के लिए ऑक्सीजन थेरेपी की सिफारिश की गई है। ऑक्सीजन उत्पादन, ढुलाई और भंडारण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर अत्यंत प्रभावकारी साबित हुए हैं।

कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति में बड़ी संख्या में व्यक्तियों को ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता को देखते हुए केवल एक ही प्रकार के सिस्टम को हासिल करना व्यावहारिक नहीं हो सकता है क्योंकि सिस्टम के बुनियादी अवयव या उपकरण बनाने वाले सभी विनिर्माण संयंत्र पहले से ही अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रहे हैं।

मौजूदा परिस्थिति में सिस्टम का उपयुक्त मिश्रण और मिलान एक उपयोगी इंतजाम साबित होगा। ऐसे समय में जब कार्बन-मैंगनीज स्टील सिलेंडरों के मौजूदा घरेलू निर्माताओं की क्षमता बेहद सीमित है, डीआरडीओ ने एक विकल्प के रूप में हल्की सामग्री वाले पोर्टेबल सिलेंडरों का उपयोग करने का सुझाव दिया है जो सामान्य ऑक्सीजन सिलेंडरों के विकल्प के रूप में बड़ी आसानी से काम में लाए जा सकते हैं। ■

प्रधानमंत्री ने गुजरात में चक्रवात 'तौकते' प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवात 'तौकते' के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति का जायज़ा लेने के लिए 19 मई को गुजरात का दौरा किया। श्री मोदी ने गुजरात और दीव स्थित उना (गिर-सोमनाथ), जाफराबाद (अमरेली), महुआ (भावनगर) में चक्रवात 'तौकते' से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया।

हवाई सर्वेक्षण के बाद उन्होंने गुजरात और दीव में राहत और पुनर्वास के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करने के लिए अहमदाबाद में एक बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने गुजरात राज्य में तत्काल राहत गतिविधियों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।

इसके बाद उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एक अंतर-मंत्रिमंडलीय टीम का गठन करेगी, ये टीम तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा करेगी, जिसके आधार पर राज्य को आगे भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

श्री मोदी ने राज्य के लोगों को आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार इस कठिन परिस्थिति में राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। केन्द्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया।

देशभर में चक्रवात 'तौकते' के कारण मरने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि के रूप में मुआवज़ा दिया जाएगा

अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री ने राज्य में कोविड महामारी की स्थिति का भी जायज़ा लिया। प्रशासन ने कोविड महामारी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से श्री मोदी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने कोविड से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी के इस गुजरात दौरे में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी और अन्य अधिकारी शामिल थे।

श्री मोदी ने भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में चक्रवात 'तौकते' से प्रभावित होने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना और इस आपदा में अपनी जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों के प्रति गहरा दुःख व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तथा दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली में चक्रवात 'तौकते' के कारण मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि के रूप में मुआवज़ा देने की घोषणा की।

श्री मोदी ने कहा कि चक्रवात के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार और प्रभावित राज्यों की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही राज्य सरकारें अपने यहां होने वाले नुकसान का आकलन केन्द्र सरकार के साझा करेंगी, उसके तुरंत बाद इन राज्यों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

श्री मोदी ने कहा कि हमें आपदा प्रबंधन से संबंधित और अधिक वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में लगातार कार्य करना होगा। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में तीव्र गति से राहत और बचाव सुनिश्चित करने के लिए अंतर-राज्य समन्वय बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक संचार तकनीकों का उपयोग करने पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया।

उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त घरों और संपत्तियों की मरम्मत करने पर भी तत्काल ध्यान देने का आह्वान किया। ■

एसीसी बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने हेतु 18,100 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 मई को 'राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैट्री भंडारण कार्यक्रम' के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को मंजूरी दे दी। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने इस योजना का प्रस्ताव रखा था। इस योजना के तहत 50 गीगावॉट ऑवर्स और पांच गीगावॉट ऑवर्स की उपयुक्त एसीसी (उन्नत रासायनिक सेल) बैट्री की निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसकी लागत 18,100 करोड़ रुपये है। विदित हो कि गीगावॉट ऑवर्स का अर्थ एक घंटे में एक अरब वॉट ऊर्जा प्रति घंटा निर्माण करना है।

एसीसी उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकी की नई पीढ़ी है, जिसके तहत बिजली को इलेक्ट्रो-केमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है। जब जरूरत पड़े, तो इसे फिर से बिजली में बदला जा सकता है। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली से चलने वाले वाहन, उन्नत विद्युत ग्रिड, सौर ऊर्जा आदि में बैट्री की आवश्यकता होती है।

आने वाले समय में इस उपभोक्ता सेक्टर में तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। उम्मीद की जाती है कि बैट्री प्रौद्योगिकी दुनिया के कुछ सबसे बड़े विकासशील सेक्टर में अपना दबदबा कायम कर लेगी।

कई कंपनियों ने इस क्षेत्र में निवेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन वैश्विक अनुपात के सामने उनकी क्षमता बहुत कम है। इसके अलावा, एसीसी के मामले में तो भारत में निवेश नगण्य है। एसीसी की मांग भारत में इस समय आयात के जरिये पूरी की जा रही है। राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक सेल (एसीसी) बैट्री भंडारण से आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे 'आत्मनिर्भर भारत' को भी मदद मिलेगी।

एसीसी बैट्री भंडारण निर्माता का चयन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिये किया जायेगा। निर्माण इकाई को दो वर्ष के भीतर काम चालू करना होगा।

प्रोत्साहन राशि को पांच वर्षों के दौरान दिया जायेगा। विशिष्ट ऊर्जा सघनता और स्थानीय मूल्य संवर्धन में बढ़ोतरी के साथ प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ा दिया जायेगा। एसीसी बैट्री भंडारण निर्माता में से प्रत्येक को यह भरोसा दिलाना होगा कि वह कम से कम पांच गीगावॉट ऑवर्स की निर्माण सुविधा सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पांच वर्षों के भीतर वह परियोजना स्तर पर मूल्य संवर्धन करेगा।

साथ ही, लाभार्थी फर्मों को कम से कम 25 प्रतिशत का घरेलू मूल्य संवर्धन करना होगा और दो वर्षों में 225 करोड़ रुपये/गीगावॉट ऑवर्स का अनिवार्य निवेश करना होगा। बाद में उसे पांच सालों के भीतर 60 प्रतिशत तक घरेलू मूल्य संवर्धन करना होगा। यह सारा काम मूल संयंत्र के स्तर पर या परियोजना स्तर पर किया जाना है, यदि परियोजना स्तर पर बुनियादी तौर पर काम हो रहा हो।

योजना से संभावित लाभ

- इस कार्यक्रम के तहत भारत में कुल 50 गीगावॉट ऑवर्स की एसीसी निर्माण सुविधा की स्थापना।
- एसीसी बैट्री भंडारण निर्माण परियोजनाओं में लगभग 45,000 करोड़ रुपये का सीधा निवेश।
- भारत में बैट्री निर्माण की मांग को पूरा करना।
- मेक इन इंडिया को बढ़ावाः घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्धन पर जोर और आयात पर निर्भरता कम करना।
- उम्मीद की जाती है कि योजना के तहत एसीसी बैट्री निर्माण से विद्युत चालित वाहन (ईवी) को प्रोत्साहन मिलेगा और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी, जिसके कारण 2,00,000 करोड़ रुपये से 2,50,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
- एसीसी के निर्माण से ईवी की मांग बढ़ेगी, जिनसे कम प्रदूषण होता है। भारत महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा एजेंडे पर पूरी ताकत से अमल कर रहा है, इसलिए एसीसी कार्यक्रम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी में कमी आयेगी। भारत इस दिशा में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये प्रतिबद्ध है। ■

असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्वा सरमा

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 10 मई 2021 को असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ उनकी कैबिनेट के 13 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। उन्हें असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी द्वारा गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, असम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब देब, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा, मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह और नगालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफियू रियो सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

श्री सरमा ने पारंपरिक 'पट रेशम' की धोती और कुर्ता धारण किया हुआ था तथा अपने गले में मुगा 'गमोसा' डाला हुआ था। उन्होंने असमिया में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

विदित हो कि 2 मई को असम विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा को लगातार दूसरी बार जीत मिली थी।

शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (एनईडीए) के संयोजक श्री हिमंत बिस्वा सरमा सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए थे। विधायक दल की बैठक में केन्द्रीय पर्यवेक्षक के नाते केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं असम प्रभारी श्री बैजयंत पांडा, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह उपस्थित थे। श्री सरमा के नाम का प्रस्ताव निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार दास और विधायक श्रीमती नंदिता गरलोसा द्वारा समर्थन किया गया।

श्री हिमंत बिस्वा सरमा का जन्म 1 फरवरी, 1969 को हुआ। उनके पिता का नाम श्री कैलाश नाथ सरमा और मां का नाम श्रीमती मृणालिनी देवी है। श्री सरमा ने गुवाहाटी के कामरुप एकैडमी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की और फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। श्री सरमा ने 1996 से 2001 के बीच गुवाहाटी हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस भी की थी। श्री सरमा ने पहली बार गुवाहाटी के जालुकबाड़ी से सन 2001 में चुनाव लड़ा। उन्होंने यहां असम गण परिषद के नेता श्री भृगु कुमार फुकान को हराया और उसके बाद से आज तक श्री सरमा इस सीट पर जीत दर्ज

करते आए हैं।

बता दें कि 126 विधान सभा सीट वाली असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 75 सीटों पर जीत मिली थी।

असम में विकास की यात्रा और तेज होगी : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने अन्य नेताओं को भी मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी।

श्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, "हिमंत बिस्वा सरमाजी और आज शपथ लेने वाले अन्य मंत्रियों को बधाई देता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि यह टीम असम में विकास की यात्रा को और तेज करने तथा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल रहेगी।"

श्री मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की भी प्रशंसा की। उन्होंने ट्वीट किया, "मेरे महत्वपूर्ण सहयोगी सर्बानंद सोनोवालजी ने पिछले पांच वर्ष एक जन समर्थक और विकास समर्थक प्रशासन का नेतृत्व किया। असम की प्रगति और राज्य में पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है।"

राजग सरकार प्रदेश की सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगी : जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी।

श्री नड्डा ने ट्विटर पर लिखा, "असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर श्री हिमंत बिस्वा सरमा जी को बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने असम सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राजग सरकार प्रदेश की सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगी।"

हम असम और पूरे उत्तर पूर्व को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे: हिमंत बिस्वा सरमा

असम के नए मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर कहा कि अपने दिल में असम की माटी की महक और खून में यहां के लोगों का बहुत प्यार लिये सभी असमी लोगों का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं, आप सभी के विश्वास से हूं। अगर आपका विश्वास मुझे नहीं मिला होता तो मैं कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज मैं असम के लिए गहरा प्यार रखते हुए आप सभी के लिए और सभी के साथ काम करने का संकल्प लेता हूं।

अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। आपके लिए मेरे मन में गहरा लगाव है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम असम और पूरे उत्तर पूर्व को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के आपके विजन को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ■

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 'सेवा ही संगठन' अभियान

राष्ट्रव्यापी 'सेवा ही संगठन' कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश के कानपुर, मेरठ, झांसी, चित्रकूट और पुडुचेरी के भाजपा कार्यकर्ता जरूरतमंदों को भोजन, राशन, फेस गार्ड, स्टीमर और अन्य आवश्यक सामान वितरित करते हुए।

एन रंगासामी ने ली पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ

एआईएनआरसी नेता श्री एन रंगासामी ने 07 मई, 2021 को पुडुचेरी के राज निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल श्रीमती तमिलिसाई सुंदरराजन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वह चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पूर्व मुख्य सचिव ने श्री रंगासामी को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की राष्ट्रपति की अधिसूचना पढ़कर सुनाई। श्री एन रंगासामी ने तमिल भाषा में शपथ ली।

शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष श्री एल मुरुगन, कर्नाटक भाजपा उपाध्यक्ष और पार्टी पुडुचेरी प्रभारी श्री निर्मल कुमार सुराणा, राज्यसभा सांसद श्री राजीव चंद्रशेखर, पुडुचेरी के सांसद श्री एन गोकुलकृष्णन उपस्थित रहे।

पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि एआईएनआरसी और भाजपा पुडुचेरी मंत्रिमंडल के विस्तार पर सहमत हुए हैं। एआईएनआरसी और भाजपा के पास तीन-तीन मंत्री पद होंगे और भाजपा को उपमुख्यमंत्री पद मिलेगा। कुछ दिनों में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एनडीए केंद्र शासित प्रदेश को तेजी से प्रगति के पथ पर ले जाएगा और लोगों से किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करेगा।

शपथ ग्रहण के बाद नए मुख्यमंत्री श्री एन रंगासामी ने कहा कि एनडीए सरकार पुडुचेरी के विकास और लोगों के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत करेगी।

एनडीए केंद्र शासित प्रदेश को तेजी से प्रगति के पथ पर ले जाएगा और लोगों से किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करेगा।

उल्लेखनीय है कि भाजपा ने 2021 के विधानसभा चुनाव में पुडुचेरी में इतिहास रच दिया। पुडुचेरी में पहली बार भाजपा और एआईएनआरसी गठबंधन ने विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया। एआईएनआरसी ने 10 सीटें जीती थीं, जबकि सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने छह सीटें हासिल की थीं। कर्नाटक के बाद, यह दक्षिण भारत का दूसरा राज्य है जहां एनडीए ने अपनी सरकार बनाई।

प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री को बधाई दी

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री एन रंगासामी को बधाई देते हुए, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्विटर संदेश में कहा, "मैं श्री एन रंगासामी जी को पुडुचेरी के सीएम के रूप में शपथ लेने पर बधाई देता हूं। आगे के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं।" ■

भारत में आया 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का सर्वाधिक एफडीआई

केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से जुड़े नीतिगत सुधारों, निवेश को सुविधाजनक बनाने और कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने के मोर्चों पर किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप देश में एफडीआई प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 24 मई को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े निम्नलिखित रुझान वैश्विक निवेशकों के बीच एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत की विशेष हैसियत की पुष्टि करते हैं:

» भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का कुल एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया है और यह पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में आकर्षित किए गए कुल एफडीआई (74.39 अरब अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।

» एफडीआई इक्विटी प्रवाह में पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2019-20 (49.98 अरब अमेरिकी डॉलर) की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 (59.64 अरब अमेरिकी डॉलर) में 19% की वृद्धि दर्ज की गई।

» शीर्ष निवेशक देशों की दृष्टि से वित्त वर्ष 2020-21 में सिंगापुर 29% के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका (23%) और मॉरीशस (9%) का नंबर आता है।

» 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर' वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में लगभग 44% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष सेक्टर के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके बाद क्रमशः निर्माण (इन्फ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना) गतिविधियों (13%) और सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर (8%) का नंबर आता है।

» 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर' सेक्टर के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में प्रमुख एफडीआई प्रवाह प्राप्तकर्ता राज्य क्रमशः गुजरात (78%), कर्नाटक (9%) और दिल्ली (5%) हैं।

» वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान गुजरात कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 37% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र (27%) और कर्नाटक (13%) का नंबर आता है।

» वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान गुजरात में अधिकांश इक्विटी प्रवाह 'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर' (94%) और 'निर्माण (अवसंरचना) गतिविधियां' (2%) सेक्टरों में हुआ है।

» वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में निर्माण (अवसंरचना) गतिविधियां, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, रबर के सामान, खुदरा व्यापार, दवाएं एवं फार्मास्यूटिकल्स और विद्युत उपकरण जैसे प्रमुख सेक्टरों में इक्विटी प्रवाह में 100% से भी अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

» वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इक्विटी प्रवाह में प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 10 देशों में सऊदी अरब शीर्ष निवेशक है। सऊदी अरब ने पिछले वित्त वर्ष में किए गए 89.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 2816.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया।

» वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान क्रमशः अमेरिका और ब्रिटेन से एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 227% और 44% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। ■

डीएपी खाद पर बढ़ाई गई 140 प्रतिशत सब्सिडी

किसानों को डीएपी पर 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़कर अब 1200 रुपये प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 मई को खाद कीमतों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें खाद कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों के कारण खाद की कीमतों में वृद्धि हो रही है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए। डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 500 रुपये प्रति बैग से 140 प्रतिशत बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बैग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।

इस प्रकार डीएपी की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों में वृद्धि के बावजूद इसे 1200 रुपये के पुराने मूल्य पर ही बेचे जाने का निर्णय लिया गया। साथ

ही, मूल्य वृद्धि का सारा अतिभार केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला किया। प्रति बोरी सब्सिडी की राशि कभी भी एक बार में इतनी नहीं बढ़ाई गई है।

पिछले साल डीएपी की वास्तविक कीमत 1,700 रुपये प्रति बोरी थी। जिसमें केंद्र सरकार 500 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी दे रही थी। इसलिए कंपनियां किसानों को 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खाद बेच रही थीं।

हाल ही में डीएपी में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। इसी कारणवश, एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपये है, जिसे खाद कंपनियों द्वारा 500 रुपये की सब्सिडी घटाकर 1900 रुपये में बेचा जाता है। आज के फैसले से किसानों को 1200 रुपये में ही डीएपी का बैग मिलता रहेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगी कि किसानों को मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव न भुगतना पड़े।

केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी। ■

35 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 701 वन स्टॉप केंद्रों के माध्यम से 3 लाख से अधिक महिलाओं को उपलब्ध हुई सहायता

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही वन स्टॉप सेंटर योजना (ओएससी) यानी एक ही छत के नीचे मदद प्रदान करने की योजना ने अब तक 3 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की है।

यह योजना 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासनों के माध्यम से लागू की जा रही है ताकि हिंसा से प्रभावित महिलाओं और निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर एक ही छत के नीचे महिलाओं को एकीकृत सहारा और सहायता प्रदान की जा सके।

इसके अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता सहित कई सेवाओं के लिए तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान की जाती है। अब तक 35 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 701 ओएससी चालू किए जा चुके हैं। ■

जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को 1,605 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान जारी

पूर्वोत्तर राज्यों के तेजी से विकास पर फोकस के साथ भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन देने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन लागू करने के लिए 1,605 करोड़ रुपए जारी किया है। यह इस वित्त वर्ष में चार भागों में जारी की जाने वाली राशि का पहला भाग है।

ग्रामीण घरों में पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए इतनी बड़ी राशि का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन सुधारने में भारत सरकार की प्राथमिकता का स्पष्ट संकेत देता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जल जीवन मिशन के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय अनुदान के रूप में 9,262 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन देने के लिए इस चुनौतीपूर्ण समय में बढ़े हुए आवंटन के साथ-साथ धन जारी किए जाने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत आवंटित केंद्रीय कोष में से 93 प्रतिशत कोष का उपयोग पेयजल आपूर्ति संरचना विकसित करने, 5 प्रतिशत का उपयोग समर्थनकारी गतिविधियों तथा 2 प्रतिशत राशि का उपयोग जल गुणवत्ता मापन तथा निगरानी गतिविधियों में उपयोग के लिए है।

केंद्रीय कोष भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों दिए गए नल के पानी के कनेक्शन और उपलब्ध केंद्रीय और समतुल्य राज्य हिस्सा के उपयोग के आधार पर जारी किया जाता है। ■

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दी गई कोविड टीके की 22 करोड़ से अधिक खुराक

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। भारत सरकार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है।

जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है।

कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई, 2021 से शुरू हो गया है। रणनीति के तहत हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50% खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसाकि पहले से किया जा रहा था।

भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 22 करोड़ से अधिक खुराक (22,16,11,940) मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत (अपव्यय सहित) 20,17,59,768 खुराक (27 मई की सुबह आठ बजे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) है।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.84 करोड़ से ज्यादा (1,84,90,522) खुराक उपलब्ध हैं, जिन्हें दिया जाना बाकी है। इसके अलावा, 11 लाख (11,42,630) खुराक प्रक्रियारत है और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दे दी जाएगी। ■

डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड-19 रोधी दवा 2-डीजी जारी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से विकसित की गयी कोविड-19 रोधी दवा 2-डीजी की पहली खेप 17 मई को जारी की। कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले तथा गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर 2-डीऑक्सी-डी-ग्लुकोज (2-डीजी) दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) की ओर से मंजूरी मिल चुकी है।

गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय ने आठ मई को एक बयान में कहा था कि 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी) के क्लीनिकल परीक्षण में पता चला है कि इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही इस दवा से मरीज जल्दी ठीक होते हैं।

कोविड-19 रोधी इस दवा को डीआरडीओ की अग्रणी प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान (इनमास) ने हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशाला के साथ मिलकर विकसित किया है। यह दवा एक सैशे में पाउडर के रूप में उपलब्ध रहेगी जिसे पानी में मिलाकर मरीजों को पीना है।

डीआरडीओ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि यह दवा कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है। उन्होंने कहा कि यह देश के वैज्ञानिक कौशल का अनुपम उदाहरण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह समय थकने और आराम करने का नहीं है क्योंकि इस महामारी के स्वरूप को लेकर कुछ भी निश्चित जानकारी नहीं है।

उन्होंने कहा कि चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति का मामला हो या आईसीयू बिस्तरों या तरल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए क्रायोजेनिक टैंकरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात हो, सरकार ने पूरी स्थिति को बेहद गंभीरता से लिया है।

2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी) के क्लीनिकल परीक्षण में पता चला है कि इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलती है

रक्षा मंत्री ने दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी और गांधीनगर में आईसीयू, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर से लैस कोविड अस्पतालों के निर्माण के अलावा, पीएम केयर्स फंड के तहत देशभर के विभिन्न अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए डीआरडीओ की सराहना की।

श्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान स्थिति से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करने में सशस्त्र बलों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना देश और विदेश से ऑक्सीजन टैंकर, कंटेनर, कंसन्ट्रेटर और अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के परिवहन के लिए अथक प्रयास कर रही हैं।

अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 2-डीजी को डीआरडीओ और डीआरएल, हैदराबाद की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया, जो कोविड-19 के रोगियों को इस बीमारी से जल्दी से उबरने में मदद करेगा और ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता कम करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह दवा न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में इस वायरस को हराने में काफी मददगार साबित होगी। उन्होंने डीआरडीओ और उसके वैज्ञानिकों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बधाई दी। ■

खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 30.544 करोड़ टन रहने का अनुमान

2020-21 के दौरान उत्पादन पिछले पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 2.666 करोड़ टन ज्यादा है

केन्द्रीय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने 2020-21 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान 25 मई को जारी किया। इसके अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 30.544 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे किसान भाइयों और बहनों के अथक प्रयासों, कृषि वैज्ञानिकों के योगदान, भारत सरकार की नीतियों और राज्य सरकारों से मिले बेहतर सहयोग और समन्वय के चलते यह सकारात्मक स्थिति बनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र के विकास पर है।

विभिन्न फसलों के उत्पादन का आकलन राज्यों से मिले आंकड़ों पर आधारित है और अन्य स्रोतों से उपलब्ध जानकारी से इसका सत्यापन किया गया है। तीसरे अग्रिम अनुमान के तहत, 2020-21 के दौरान प्रमुख फसलों का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है:

खाद्यान्न – 30.544 करोड़ टन (रिकॉर्ड)

» चावल – 12.146 करोड़ टन। (रिकॉर्ड)

» गेहूं – 10.875 करोड़ टन। (रिकॉर्ड)

पोषक तत्व/मोटे अनाज – 4.966 करोड़ टन

» मक्का – 3.024 करोड़ टन। (रिकॉर्ड)

» दालें – 2.558 करोड़ टन।

» तुअर – 0.414 करोड़ टन।

» चना – 1.261 करोड़ टन। (रिकॉर्ड)

तिलहन – 3.657 करोड़ टन

» मूंगफली – 1.012 करोड़ टन। (रिकॉर्ड)

» सोयाबीन – 1.341 करोड़ टन।

» रेपसीड और सरसों – 0.999 करोड़ टन। (रिकॉर्ड)

गन्ना – 39.280 करोड़ टन।

कपास – 3.649 करोड़ गांठें (प्रत्येक 170 किग्रा)

जूट और मेस्टा – 0.962 करोड़ गांठें (प्रत्येक 180 किग्रा)

2020-21 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के तहत देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 30.544 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो 2019-20 के दौरान हुए कुल 29.75 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 79.4 लाख टन ज्यादा है। इसके अलावा 2020-21 के दौरान उत्पादन पिछले पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 2.666 करोड़ टन ज्यादा है।

वर्ष 2020-21 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 12.146 करोड़ टन रहने का अनुमान है। यह विगत 5 वर्षों के 11.244 करोड़ टन औसत उत्पादन की तुलना में 90.1 लाख टन अधिक है।

वर्ष 2020-21 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 10.875 करोड़ टन अनुमानित है। यह विगत पांच वर्षों के 10.042 करोड़ टन औसत गेहूं उत्पादन की तुलना में 83.2 लाख टन अधिक है।

पोषक/मोटे अनाजों का उत्पादन 4.966 करोड़ टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के दौरान हुए 4.775 करोड़ टन उत्पादन की तुलना में 19.1 लाख टन अधिक है। इसके अलावा, यह औसत उत्पादन की तुलना में भी 56.8 लाख टन अधिक है।

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 2.558 करोड़ टन अनुमानित है जो विगत पांच वर्षों के 2.193 करोड़ टन औसत उत्पादन की तुलना में 36.4 लाख टन अधिक है।

2020-21 के दौरान कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 3.657 करोड़ टन अनुमानित है जो 2019-20 के दौरान 3.322 करोड़ टन उत्पादन की तुलना में 33.5 लाख टन अधिक है। इसके अलावा, 2020-21 के दौरान तिलहनों का उत्पादन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 60.2 लाख टन अधिक है।

वर्ष 2020-21 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन 39.280 करोड़ टन अनुमानित है। वर्ष 2020-21 के दौरान गन्ने का उत्पादन औसत गन्ना उत्पादन 36.207 करोड़ टन की तुलना में 3.073 करोड़ टन अधिक है।

कपास का उत्पादन 3.649 करोड़ गांठें (प्रति 170 किग्रा की गांठें) अनुमानित हैं, जो औसत कपास उत्पादन की तुलना में 45.9 लाख गांठें अधिक है। ■

राष्ट्र का अर्थ

दीनदयाल उपाध्याय

दूसरा और अंतिम भाग...

आज लोग देश को एक राजनीतिक स्वरूप में देखते हैं और एक राज्य को ही एक देश कहते हैं। यदि एक राज्य के दो राज्य बन गए तो दो देश हो गए, जैसे भारत और पाकिस्तान। अंग्रेज के 'कंट्री' शब्द का राजनीतिक इकाई के साथ समीकरण करके रख दिया है। यह दोनों एक मान लिए गए हैं। यह ठीक है कि एक देश में एक ही राज्य हो। यह एक आदर्श है, किंतु यह आदर्श प्राप्त नहीं हुआ, तब भी एक राज्य को देश कह देना गलत है।

यह तर्कहीनता है। यह सोचना ही गलत है कि एक राज्य को पहले एक देश मान लिया जाए और फिर कहा जाए कि उसके रहनेवाले एक राष्ट्र हैं। यदि उनमें राष्ट्र को बनानेवाली चीज़ें नहीं हैं तो बनाई जानी चाहिए। पर यह उलटी रीति से सोचने का ढंग है। वास्तव में सोचना इस प्रकार से चाहिए कि एक देश में एक राष्ट्र होता है। एक देश में दो राष्ट्र नहीं हो सकते। दूसरा होगा तो या तो वह उस देश पर शासन करनेवाला, गुलाम बनानेवाला होगा या फिर शरणार्थी होगा। जैसे एक घर में दो स्वामी, एक जंगल में दो शेर, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकतीं, उसी प्रकार एक देश में दो राष्ट्र नहीं हो सकते। अतः प्रयत्न यह हो कि एक देश या राष्ट्र में एक ही राज्य हो।

पर कभी-कभी ऐसा होता है, जब आदर्श प्राप्त नहीं होता है। उस समय जो कुछ मिलता है, उसी को ठीक समझकर चलने लगते हैं। जैसे कोई कर्मचारी सोचता है कि मैं घूस नहीं लूंगा, पर कभी आगे चलकर फिसल जाता है और घूस ले लेता है, तो घूस लेने को ही न्यायोचित ठहराने लगता है। अंग्रेज़ी कवि गोल्डस्मिथ ने कहा है, सभी कुछ यहां दुनिया की राजनीति के कारण हुआ।

सीधी तरह विचार करने पर ज्ञात होता है कि राष्ट्र मानवों के उस समूह को कहते हैं, जो एक देश में निवास करता है। देश की राजनीतिक सीमाएं शक्ति के अनुसार घट-बढ़ सकती हैं। कुछ वर्ष पूर्व पाकिस्तान हमारे देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत था, काफी

पहले अफगानिस्तान भी था। अभिप्राय यह कि राजनीतिक सीमाएं घट-बढ़ सकती हैं। फिर यदि राजनीतिक सीमाएं नहीं, तो राष्ट्र की या देश की दूसरी सीमाएं कौन-सी हैं?

राष्ट्र के लिए देश में निवास करना ही पर्याप्त नहीं है। निवास करनेवाले तो अनेक हो सकते हैं, जैसे अंग्रेज भी यहां निवास करते हैं। किंतु राष्ट्र उन लोगों से बनता है, जो एक भूमि में निवास करते हैं, और उस भूमि को अपनी समझते हैं, निवास न भी करते हों, तो भी उसे अपनी समझते हों। 'अपने' का भी भाव माता और पुत्र का सा होना चाहिए। यों तो अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान को अपना समझते थे, पर वे अपने को इसका स्वामी समझते थे। किंतु हम अपने को इस भूमि का पुत्र कहते हैं और माता के नाते स्वीकार करते हैं।

हमने राष्ट्र को अपनी माता के रूप में माना है। अतः जिस भूभाग के संबंध में हमारा मातृभाव है, वह हमारा देश है, चाहे फिर वह राजनीतिक दृष्टि से घट-बढ़ गया हो। अतः राष्ट्र उन मानवों का समूह है, जो किसी भूखंड के प्रति मातृभाव लेकर चलता है। यह हमारी मां है, इसकी गोद में आकर बैठेंगे, गौरव और स्वतंत्रता के साथ बैठेंगे। यदि आज किसी कारण से उस गोद में बैठने से वंचित हो गए तो ध्रुव के समान तपस्या की भावना लेकर बैठने की इच्छा से चलेंगे। यह कल्पना, यह भावना, जिस मानव समूह में हो, वह एक राष्ट्र है।

एक बात और भी है। किसी भी भूखंड के प्रति भाव मानव-समूह लेकर चले तो प्रश्न हो सकता है कि अलग-अलग टुकड़ों के बारे में यह भाव हो जाए, जैसे राजस्थान, बंगाल आदि। किंतु इसके आगे भी एक चीज़ होती है। यह मातृभावना लेकर चलनेवाला मानव समाज एक अन्य भाव से भी जुड़ा होता है, वह है संस्कृति। संस्कृति के कारण ही उस भूखंड के प्रति मातृभावना प्रकट होती है।

सामान्य रूप से समझने के लिए यह संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। पर आत्मा के स्थान पर संस्कृति से भी आगे की एक चीज़ है। संस्कृति तो शरीर है। वैसे व्याकरण के अनुसार 'मनुष्य' व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामप्रसाद एक व्यक्ति है। अब रामप्रसाद व्यक्तिवाचक एकवचन है। पर रामप्रसाद क्या है? यह एक बड़ी समस्या है। बच्चों के छूने के खेल के समान मानो रामप्रसाद एक व्यक्ति से कहता है, मुझे छुओ, बच्चों ने उसके हाथ को

छुआ। तो रामप्रसाद कहां है? रामप्रसाद नाम है तो नाम तो उससे जुड़ गया है। दूसरा नाम रख दें, उसके स्थान पर तो वह दूसरा नाम हो जाएगा। यह शरीर भी रामप्रसाद नहीं।

इसके आगे भी कोई चीज़ है, वह है उसका व्यक्तित्व। मरने के बाद हम मनुष्य के शरीर का स्मरण नहीं करते, उसके व्यक्तित्व का, गुणों का, कर्मों का वर्णन करते हैं। उसके कर्मों से, गुणों से व्यक्तित्व बनता है। पर वह असलियत नहीं, आत्मा नहीं। आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा व्यक्तित्व से अलग है। जब मनुष्य पैदा हुआ तो कर्म लेकर या व्यक्तित्व लेकर नहीं पैदा हुआ। व्यक्तित्व तो पैदा किया जाता है। जन्म लेने के बाद बड़े होने पर कर्म करते-करते गुणों से मिलकर व्यक्तित्व बनता है। पर आत्मा तो मूल में होती है। वह इससे भी आगे की वस्तु है, जो आगे विकसित होती है।

राष्ट्र एक सजीव इकाई है, निर्जीव इकाई नहीं। राष्ट्र में जीवन है, व्यक्ति के समान चैतन्य है। अपने यहां प्राचीन काल में भी यही मानते थे। आज के मनोवैज्ञानिक भी इसे समझने लगे हैं। जैसे व्यक्तित्व का एक भाग मस्तिष्क सब में है, कुत्ते में भी और पेड़-पौधों में भी। ऐसे प्रयोग किए गए हैं, जिनसे सिद्ध हुआ है कि संगीत से पेड़-पौधे भी बड़े होते हैं और उनमें अच्छे फल आते हैं। इस प्रकार सुख-दुःख और आनंद का अनुभव वनस्पति को भी होता है।

यह सोचने की ताकत सब में होती है, ऐसे ही समूह-मस्तिष्क (ग्रुप माइंड) भी होता है। जिस प्रकार हर व्यक्ति का अपना सोचने का अलग ढंग होता है, उसी प्रकार समूह का भी अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है। समूह की यह जो अलग सत्ता होती है, उसमें भी जीवमान सत्ता है। तभी वह प्रेरणा देती है। क्योंकि जीवमान वस्तु ही प्रेरणा देती है। मोटर चलती है, पर जीवनमान नहीं, अतः वह प्रेरणा नहीं दे सकती। जीवनमान वस्तु में स्वतः ही इच्छाशक्ति, स्वतः की चेतना, कर्मशक्ति तथा सत्ता की भावनाओं का समुच्चय होता है। इसी प्रकार राष्ट्र का एक जीवमान समुच्चय होता है। इसीलिए राष्ट्र पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। जैसे व्यक्ति या कोई भी जीव मात्र उत्पन्न होता है, बनाया नहीं जाता, वैसे ही राष्ट्र बनाया नहीं जाता, उत्पन्न होता है, बढ़ता है और नष्ट भी जीवनमान वस्तु के समान होता है।

अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्र का चैतन्य क्या है? उसके लिए संस्कृत का एक शब्द है, वह कठिन है। वह है, 'चिति'। उसे हम राष्ट्र की आत्मा कह सकते हैं। एक 'चिति' को लेकर एक राष्ट्र पैदा होता है। उसके लिए मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करते हैं और कर्मों से मनुष्य का व्यक्तित्व बनता है। उससे व्यक्ति के अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म वे होते हैं, जो व्यक्ति को उदात्त बनाते हैं, जिससे उसका विकास होता है। 'चिति' अर्थात् आत्मा का साक्षात्कार करनेवाले अच्छे कर्म और जो ऐसे नहीं हैं, वे बुरे कर्म। इसी प्रकार, राष्ट्र की उन्नति जिससे होती है, वह है उसकी संस्कृति। जो कर्म राष्ट्र को 'चिति' का साक्षात्कार कराते हैं, वे संस्कृति हैं। जो बुरे कर्म हैं, वे विकृति हैं। राम व कृष्ण के कर्म संस्कृति हैं। रावण व दुर्योधन के नहीं।

राम और कृष्ण विजयी हुए, इसी कारण उनके कर्मों को ठीक मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। उगते सूर्य को ही नमस्कार करते हैं, ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज, पद्मिनी और प्रताप को भी हम बड़ा कहते हैं। इसमें हमारे जीवन की एक दृष्टि है जो हमारी 'चिति' से बनती है। उसके अनुकूल जो कार्य होते हैं, उनसे हमारी संस्कृति बनती है।

इस प्रकार राष्ट्र बनता है। जिस प्रकार एक मनुष्य की आत्मा होती है, वह कर्म करता है, अच्छे कर्मों को पुण्य के नाते जोड़ता है, बुरे कर्मों को हटाने का प्रयत्न करता है। यद्यपि बुरे कर्मों का भी दुष्परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है, पर प्रेरणा अच्छे कर्मों से ही लेता है। इसी प्रकार मनुष्यत के व्यक्तित्व के समान राष्ट्र का एक व्यक्तित्व बनता है। राष्ट्र एक जीवमान इकाई है, जो अपनी आत्मा या 'चिति' को लेकर पैदा होती है। उसका 'चिति' के अनुसार साक्षात्कार करानेवाली सभी कृतियां संस्कृति हैं। यह संस्कृति पैदा होती है, बढ़ती है। उस आधार पर यह राष्ट्रि खड़ा होता है। मातृभाव की भूमि पर खड़ा रहता है, कर्म करता है, भौतिक जीवन के व्यवहार में समृद्धि लाता है, मकान आदि बनते हैं, राज्य निर्मित होते हैं। समाज व्यवस्थाएं बनती हैं। यह सब सभ्यता है। जिस प्रकार मनुष्य कोई चित्र बनाता है तो उसके अंदर की जो भावना है, उसके अनुकूल वह चित्र बनाता है, इसी प्रकार राष्ट्र के अंदर की वस्तु संस्कृति-सभ्यता के रूप में प्रकट होती है।

इसी प्रकार इन संबंधों के आधार पर एक इतिहास का निर्माण होता है। जब राष्ट्रों का परस्पर संबंध आता है, तो संघर्ष होते हैं। विजय होती है, पराजय भी होती है। जिस-जिस ने इसकी संस्कृति को बढ़ाया, पोषण के नाते खड़े हुए, वे महापुरुष बनकर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार एक मानव समाज होता है, एक देश, एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक इतिहास होते हैं तो वह राष्ट्र हो जाता है। उस समाज के महापुरुष एक होते हैं। उनके आदर्श-आकांक्षाएं एक हो जाती हैं। उनके भूत, वर्तमान और भविष्य एक हो जाते हैं। यदि एक नहीं हों तो समझना चाहिए कि कहीं गड़बड़ है। यह एक वैज्ञानिक दृष्टि से विचार है। दुनिया में अन्यत्र भी जहां तार्किक दृष्टि से विचार हुआ है, यही निष्कर्ष निकला है।

(संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग, अजमेर; मई 28, 1963) ■

नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री चमन लाल गुप्ता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई, 2021 को जम्मू के गांधी नगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। कुछ दिन पहले श्री गुप्ता कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे और सफल उपचार के बाद घर लौट आए थे।

श्री गुप्ता 87 साल के थे। श्री गुप्ता के परिवार में उनके दो बेटे और एक बेटी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि श्री चमन लाल गुप्ता अनगिनत सामुदायिक सेवा के लिए याद किए जाएंगे। वह एक समर्पित विधायक थे और उन्होंने पूरे जम्मू एवं कश्मीर में भाजपा को सुदृढ़ बनाया। उनके निधन पर दुःखी हूं। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों तथा समर्थकों के साथ हैं।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी के निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। यह हमारे लिए अपूरणीय क्षति है। इस दुःख की घड़ी में परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रो. चमन लाल गुप्ता जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुःख हुआ। वह एक अनुभवी राजनेता और व्यापक रूप से सम्मानित व्यक्ति थे। उनका निधन राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है। श्री सिन्हा ने कहा कि लोगों के कल्याण हेतु उनके अपार योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

जीवन-परिचय

श्री चमन लाल गुप्ता का जन्म 13 अप्रैल, 1934 को जम्मू में हुआ था। उन्होंने जीएम साइंस कॉलेज जम्मू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएससी किया था। वह पहली बार 1972 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सदस्य बने। वे 2008 से 2014 तक भी विधानसभा के सदस्य रहे। श्री गुप्ता दो बार जम्मू-कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष भी रहे।

श्री चमन लाल गुप्ता 1996 में जम्मू के उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए और 1998 तथा 1999 में भी उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की। ■

मणिपुर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एस. टिकेंद्र सिंह का निधन

मणिपुर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री सैखोम टिकेंद्र सिंह का 13 मई की देर रात को इम्फाल में कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया। श्री सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मणिपुर भाजपा अध्यक्ष प्रो. एस. टिकेंद्र सिंह के निधन से दुःखी हूं। उन्हें एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने मणिपुर में पार्टी को मजबूत किया। वे कई सामाजिक सेवाओं में सक्रिय थे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मणिपुर भाजपा अध्यक्ष स्वर्गीय प्रो. सैखोम टिकेंद्र सिंह के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। भाजपा को मजबूत करने के उनके प्रयासों को हमेशा याद किया जाएगा। दुःख की इस घड़ी में पूरी भाजपा उनके परिवार के साथ खड़ी है।

साथ ही, श्री नड्डा और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने 15 मई को प्रो. सैखोम टिकेंद्र सिंह के लिए आयोजित एक वर्चुअल शोक सभा में भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ■

पीएम-किसान योजना से पहली बार पश्चिम बंगाल के किसान होंगे लाभान्वितः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत 9,50,67,601 लाभार्थी किसानों को 2,06,67,75,66,000 रुपये के वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लाभार्थियों के साथ बात भी की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी उपस्थित थे।

श्री मोदी ने कहा कि पहली बार पश्चिम बंगाल के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने उन किसानों के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इस महामारी के दौरान कठिनाइयों के बीच खाद्यान्न और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक साल एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड भी बना रही है।

श्री मोदी आगे बताया कि अब तक पिछले साल की तुलना में इस साल एमएसपी पर लगभग 10 प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद की गई है। अब तक गेहूं की खरीद के लिए लगभग 58,000 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में पहुंचे हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि सरकार खेती में नए समाधान और नए विकल्प प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देना भी इनमें से एक प्रयास है। जैविक खेती से अधिक लाभ पहुंचता है और अब युवा किसानों द्वारा पूरे देश में

इसे अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब गंगा के दोनों किनारों पर और इसके 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती की जा रही है, जिससे गंगा साफ रहे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9,50,67,601 लाभार्थी किसानों को 2,06,67,75,66,000 रुपये के वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस महामारी के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड की समय-सीमा बढ़ा दी गई है और किस्तों को अब 30 जून तक नवीनीकृत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 2 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

श्री मोदी ने कहा कि सदी में एक बार आने वाली यह महामारी विश्व को चुनौती दे रही है, क्योंकि यह हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी पूरी ताकत से कोविड-19 से लड़ रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि राष्ट्र के दर्द को कम करने के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग दिन-रात काम कर रहे हैं।

श्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर तीव्र गति से अधिक से अधिक देशवासियों का टीकाकरण करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में अब तक लगभग 18 करोड़ टीके की खुराकें दी जा चुकी हैं। देशभर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है।

श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जब उनकी बारी आए तो वे टीका के लिए पंजीकरण कराएं और हर वक्त कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह टीका कोरोना से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन है और यह गंभीर बीमारी के जोखिम को कम करेगा।

उन्होंने ग्रामीण इलाकों में भी कोविड-19 के फैलने को लेकर चेतावनी दी और ग्राम पंचायतों से अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त जागरूकता और स्वच्छता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। ■

मोदीजी ने भारत को विश्व शक्ति बनाया

रघुवर दास

श्री नरेन्द्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनानेवाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सात साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री नरेन्द्र मोदी की सत्ता में सात साल पूरा करने की उपलब्धि को किस रूप में देखा जाना चाहिए? उनकी सत्ता उपलब्धि की पड़ताल किन-किन प्रसंगों को आधार बनाकर किया जाना चाहिए? क्या श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में राष्ट्रवाद मजबूत हुआ है, क्या देश की अस्मिता का संरक्षण हुआ है, क्या हमारी सीमाएं शत्रु देशों से सुरक्षित हुई हैं, क्या हमारी सेना आधुनिक युद्ध हथियारों से लैस हुई है? क्या वैश्विक नियामकों को गतिशील बनाने में भारत की उपलब्धियां सर्वश्रेष्ठ रही है? इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध विवाद में भारत की भूमिका भारत के राष्ट्रवादी नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रही थी या नहीं? कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में श्री नरेन्द्र मोदी ने अग्रणी भूमिका किस प्रकार से निभाई है? क्या गरीब और विकासशील देशों की वैक्सीन मैत्री कर सनातन संस्कृति के मूलमंत्र "वसुधैव कुटुम्बकम" के अनुरूप कार्य किया? क्या कोरोना काल में मजदूर किसान के हित और उनकी जरूरतों को पूरा करने में श्री नरेन्द्र मोदी की भूमिका बेमिसाल मानी जानी चाहिए?

सबसे पहले मोदी विरोधी विपक्ष की अफवाहों, आरोपों और हिंसक सक्रियता की पड़ताल होनी चाहिए। जहां तक मोदी विरोधियों की अफवाहों और शोर की बात है, तो विपक्ष बार-बार पराजित हो रहा है। भारत में श्री नरेन्द्र मोदी पहले ऐसे राजनेता हैं, पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सर्वाधिक जहरीला और अफवाहपूर्ण विरोध को झेला है, अंतरराष्ट्रीय विरोध और प्रतिबन्ध को झेला है। श्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करते-करते कई विरोधी देश के विरोधी

श्री नरेन्द्र मोदी ने धारा 370 समाप्त कर दिया। दुनिया को यह बता दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत अपनी संवैधानिक और सुरक्षा जरूरतों के लिए कश्मीर में कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है

हो गए। कोई पाकिस्तान की बोली बोलने लगा, तो कोई श्री नरेन्द्र मोदी को पराजित करने के लिए पाकिस्तान-चीन से मदद मांगने लगा। सर्वविदित है कि कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान जाकर श्री नरेन्द्र मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान की भाषा बोलते रहे हैं। वैश्विक वैक्सीन की उपलब्धि पर विपक्षी दलों ने क्या-क्या नहीं कहा? इतना तक कह डाला कि श्री नरेन्द्र मोदी की वैक्सीन जो लगाएगा, वह नपुंसक हो जाएगा। इतने सारे विरोध के बावजूद मोदीजी विचलित नहीं हुए। चुपचाप रहना, अपने काम पर ध्यान देना, अपने काम और अपनी उपलब्धियों से ही विरोधियों को जवाब देना उनके काम का तरीका है। अपने काम और अपनी उपलब्धियों से ही वे विपक्ष का शिकार करते हैं।

राष्ट्रवाद के प्रसंग में श्री नरेन्द्र मोदी की उपलब्धि महान है। हमें खंडित देश मिला था। मजहब के आधार पर देश का विभाजन हुआ। पाकिस्तान एक नया मजहबी देश बना। अंग्रेजों की साजिश का हम शिकार हुए। अंग्रेजों की साजिश में कश्मीर का प्रश्न राष्ट्र के लिए खतरनाक बन गया, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती और अति पाकिस्तान प्रेम के कारण कश्मीर का प्रश्न अंतरराष्ट्रीय बन गया। कई दशकों तक कश्मीर में विखंडनकारी शक्तियां हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को रौंदती रहीं। कश्मीर में भीषण आतंकवाद का दौर चला, पाकिस्तान ने कश्मीर को लूटने के लिए कोई एक नहीं बल्कि तीन-तीन युद्ध लड़ा। कश्मीर में विखंडनवादी शक्तियों से लड़ते-लड़ते डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए थे। जनसंघ ने कश्मीर में धारा 370 हटाने और राष्ट्रवाद की नींव मजबूत करने का सपना देखा था।

आप याद कीजिए फारूक अब्दुल्ला को, आप याद कीजिए उमर अब्दुल्ला को, आप याद कीजिए महबूबा मुफ्ती को,

जिन्होंने कहा था कि धारा 370 हटाने की श्री नरेन्द्र मोदी की औकात नहीं है। कश्मीर से धारा 370 हटी, तो फिर कश्मीर के अंदर में हिंसक विरोध होगा। तिरंगे झंडे को उठानेवाला कोई नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने अपनी आतंकवादी शक्ति का भय दिखाया था। कुछ मुस्लिम देशों की ओर से भी धमकियां आई थी, देश के गद्दारों ने भी धमकियां दी थीं कि अगर कश्मीर की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ तो फिर भारत की एकता और अखंडता भी खंडित हो जाएगी, इसके अलावा कश्मीर के लोग विद्रोह कर देंगे।

श्री नरेन्द्र मोदी पक्के राष्ट्रभक्त हैं। एक राष्ट्रभक्त के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि होता है। राष्ट्र की सुरक्षा एवं राष्ट्र की अस्मिता ही महत्वपूर्ण होता है। श्री नरेन्द्र मोदी ने धारा 370 समाप्त कर दिया। दुनिया को यह बता दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत अपनी संवैधानिक और सुरक्षा जरूरतों के लिए कश्मीर में कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। कश्मीर में आतंकवादी हिंसा और राष्ट्र विरोधी शक्तियों की हिंसा को जमींदोज कर दिया गया। हमारी सेना ने कश्मीर में धारा 370 हटाने के खिलाफ हिंसक आतंकवादियों और पाकिस्तानपरस्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की, जिसके कारण कश्मीर के अंदर राष्ट्रवाद निरंतर मजबूत होता चला गया और आतंकवादी शक्तियां, भारत विरोधी मजहबी शक्तियां, पाकिस्तानपरस्त लोग निरंतर कमजोर होते चले गए। हाशिए पर खड़े होते चले गए। कश्मीरी पंडित जो अपने घरों से खदेड़ दिए गए थे, वे देश के कोने कोने में आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके बीच में आशा की किरण जगी है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की योजना तैयार है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी सुनिश्चित है। कश्मीर में धारा 370 को हटाने की कूटनीति में भी श्री नरेन्द्र मोदी को महान जीत मिली।

कोई भी राष्ट्र देशद्रोहियों को संरक्षण देकर महान नहीं बन सकता है। अपनी संप्रभुता का संरक्षण नहीं कर सकता है। अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए देशद्रोहियों का दमन जरूरी है। मोदी सरकार ने सीएए कानून लागू किया। सीएए कानून के खिलाफ राष्ट्रद्रोहियों ने किस प्रकार से साजिश रची थी और प्रायोजित विरोध प्रदर्शन करवाएं, यह भी जगजाहिर है। श्री नरेन्द्र मोदी ने दृढ़ता दिखाई, सीएए कानूनों को वापस लेने से दृढ़ता से इंकार कर दिया। सीएए कानून से उन विदेशी ताकतों को

कोरोना काल में किसान मजदूरों और अन्य गरीबों को श्री नरेन्द्र मोदी ने नगद राशि, राशन, रसोई गैस उपलब्ध कराई है। देश के करोड़ों गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है

एक सबक मिला है, जो भारत को सराय मान बैठे हैं। अभी-अभी मोदी सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य मजहबी हिंसक देशों से आए हिंदुओं को नागरिकता आवेदन देने के लिए आमंत्रित किया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं की पीड़ा और अपमान अब समाप्त होगा।

मोदी सरकार में किसानों को हरसंभव मदद की कोशिश हुई है। किसानों के बैंक खाते में हर साल 6000 रुपए जमा हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममताजी ने जहां इस योजना को लागू करने से इंकार कर दिया था, वहां भी अब किसानों को यह सुविधा मिल गई है। ममता बनर्जी अब इस योजना को लागू करने के लिए बाध्य हुई है। खाद बोरी पर सब्सिडी को पांच सौ से बढ़ाकर बारह सौ रुपए कर दिए गए हैं। कृषि कानून देश हित और किसान हित में है। सभी श्रेणी के किसानों को इससे लाभ मिलेगा, पर विपक्ष ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को भड़काने का काम किया। विदेशी शक्तियां भी किसानों को भड़काने में लगी रहीं। किसानों के कथित आंदोलन में घुसपैठ कर बाहरी लोगों ने हिंसा फैलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लाल किले पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई। फिर भी श्री नरेन्द्र मोदी ने संयम से काम लिया। किसानों के आंदोलन पर श्री नरेन्द्र मोदी ने कोई सख्ती नहीं दिखाई। याद कीजिए आप बाबा रामदेव के आंदोलन को, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठी चलवाई और रामलीला मैदान से बाबा रामदेव को खदेड़ दिया गया था।

भारत का विपक्ष श्री नरेन्द्र मोदी पर वैक्सीन को लेकर आरोप लगाता रहा था कि पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन खोजने में व्यस्त है, पर मोदीजी चुपचाप बैठे हुए हैं। मोदीजी की तैयारी और कर्मठता से दुनिया तब चमत्कृत हुई, जब श्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि हमने एक नहीं बल्कि दो-दो वैक्सीन बनाई है। भारत की वैक्सीन उपलब्धि पर जहां पूरी दुनिया श्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा कर रही थी, वही भारत का विपक्ष विदेशी हाथों में खेल रहा था। भारतीय वैक्सीन के खिलाफ अभियान चलाया गया। यहां तक कहा गया कि मोदीजी ने मुसलमानों को प्रताड़ित करने, मारने और नपुंसक

बनाने के लिए वैक्सीन बनवाई है। भारत ने पड़ोसी देशों और विकसित देशों को भी वैक्सीन दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी जरूर हुई पर मोदीजी ने जल्द ही ऑक्सीजन की कमी को दूर कर दिया और कोरोना की दूसरी लहर को भी थाम लिया।

कोरोना काल में किसान मजदूरों और अन्य गरीबों को श्री नरेन्द्र मोदी ने नगद राशि, राशन, रसोई गैस उपलब्ध कराई है। देश के करोड़ों गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है।

मोदीजी जहां देश के विकास में लगे हुए हैं, वहीं विपक्ष की राज्य सरकारें सिर्फ समस्या खड़ी कर रही हैं। अपनी नाकामी को मोदीजी के सिर पर मढ़ने का काम कर रही हैं। इससे खुद उन राज्यों का विकास बाधित होता है। निश्चित तौर पर श्री नरेन्द्र मोदी भारत को दुनिया की एक महान शक्ति के रूप में स्थापित करने के अहर्निश प्रयास में लगे हुए हैं। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं।)

खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए बनी खरीफ रणनीति, 2021

तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत भारत सरकार ने खरीफ सत्र, 2021 के लिए किसानों को मिनी किट्स के रूप में बीजों की ऊंची उपज वाली किस्मों के मुफ्त वितरण की महत्वाकांक्षी योजना को स्वीकृति दी।

विशेष खरीफ कार्यक्रम के माध्यम से तिलहन के अंतर्गत अतिरिक्त 6.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आ जाएगा और 120.26 लाख क्विंटल तिलहन और 24.36 लाख टन खाद्य तेल के उत्पादन का अनुमान है।

तिलहन में आत्मनिर्भर बनने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को उनके खेतों में इस्तेमाल के लिए ज्यादा उपज वाली किस्मों के बीजों की उपलब्धता बढ़ाकर तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। इस क्रम में अप्रैल, 2021 में हुई एक वेबिनार में राज्य सरकारों के साथ और 30 अप्रैल, 2021 को खरीफ सम्मेलन में भी विस्तार से चर्चा हुई थी।

इन विचार विमर्श के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन और ताड़ का तेल) के अंतर्गत मुफ्त में ज्यादा पैदावार वाले बीजों की किस्मों के मुफ्त वितरण पर जोर के साथ सोयाबीन और मूंगफली के लिए क्षेत्र और उत्पादकता दोनों में बढ़ोतरी की रणनीति इस प्रकार हैः

» 76.03 करोड़ रुपये की लागत से और 1,47,500 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 41 जिलों के लिए सहरोपण के उद्देश्य से सोयाबीन के बीजों का वितरण।

» 104 करोड़ रुपये की लागत से और 3,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करने के लिए 8 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के 73 जिलों में ज्यादा संभावना वाले जिलों के लिए सोयाबीन के बीजों का वितरण।

» 40 करोड़ रुपये की लागत से 9 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार के 90 जिलों में मिनी किट्स का वितरण। इससे 1,006,636 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया जाएगा और 8,16,435 मिनी किट्स का वितरण किया जाएगा।

» वितरित किए जाने वाले सोयाबीन बीजों की पैदावार 20 क्विंटल/हेक्टेयर से कम नहीं होगी। सहरोपण और ज्यादा संभावनाओं वाले जिलों के लिए बीजों का वितरण राज्य बीज एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा और मिनी किट्स के लिए बीजों का वितरण केन्द्रीय बीज उत्पादक एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

» 13.03 करोड़ रुपये की लागत से बीजों, जिनकी पैदावार 22 क्विंटल/हेक्टेयर कम न हो, के 7 राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 74,000 मूंगफली बीज मिनी किट्स का वितरण। ■

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ईपीएफओ के तहत कुल 77.08 लाख नए खाते जुड़े

ईपीएफओ के 20 मई, 2021 को प्रकाशित पेरोल के अनंतिम आंकड़े के अनुसार ईपीएफओ ने मार्च, 2021 के महीने में लगभग 11.22 लाख नए खातों को जोड़ा है। कोविड-19 महामारी के बावजूद नए खातों की संख्या में कुल 77.08 लाख की बढ़ोतरी हुई है, जो वित्त वर्ष 2021 के लिए नए खातों की लगभग पिछले साल के बराबर की बढ़ोतरी है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेरोल के त्रैमासिक आकलन से संकेत मिलता है कि कोविड-19 महामारी के संकट के कारण पहली तिमाही में असर पड़ा था, इसके बाद दूसरी तिमाही से नए जुड़ने वाले खातों की संख्या में लगातार सुधार हुआ है। तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2020) की तुलना में चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2021) में 37.44% की बढ़ोतरी के साथ 33.64 लाख नए खाते जुड़े, जो अधिकतम सुधार था।

मार्च, 2021 के महीने में जुड़े 11.22 लाख नए खातों में लगभग 7.16 लाख नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आए हैं। लगभग 4.06 लाख पुराने खाते ईपीएफओ से अलग हुए और ईपीएफओ के दायरे में आने वाले दूसरे प्रतिष्ठानों में अपनी नौकरी बदलने के बाद ईपीएफओ से दोबारा जुड़ गए। उन्होंने अंतिम रूप से पैसे निकालने की जगह पर फंड ट्रांसफर के जरिए अपनी सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प चुना।

ईपीएफओ से अलग होने वाले खातों का आंकड़ा व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों की ओर से पेश निकासी के दावों और नियोक्ताओं की ओर से अपलोड एक्जिट डेटा पर आधारित हैं, जबकि नए खातों की संख्या सिस्टम में बने नए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) पर आधारित है और

मार्च, 2021 के महीने में जुड़े 11.22 लाख नए खातों में लगभग 7.16 लाख नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आए हैं

जिससे नॉन-जीरो यानी सक्रिय खातों की जानकारी मिलती है।

पेरोल के आंकड़ों का आयु वर्ग आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि मार्च, 2021 महीने में सबसे ज्यादा 22-25 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 3.14 लाख नए खाते जुड़े हैं। इसके बाद 18-21 आयु वर्ग है, जिससे लगभग 2.29 लाख नए खाते जुड़े हैं। मार्च, 2021 में जुड़े अतिरिक्त खातों में 18-25 आयु वर्ग के सदस्यों का लगभग 48.44% योगदान रहा है। इन आयु वर्ग के सदस्यों को बाजार में नया कामकाजी हाथ माना जाता है और यह किसी व्यक्ति की आय क्षमता के मामले में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक होता है।

वित्त वर्ष 21 का जेंडर आधारित आकलन अक्टूबर, 2020 से लेकर वित्त वर्ष के खत्म होने तक महिला खाता धारकों के अनुपात में बढ़ोतरी दर्शाता है। मार्च, 2021 के महीने में लगभग 2.42 लाख महिला खाते जुड़े हैं, जो कुल जुड़े नए खातों का 21.56 फीसदी है।

फरवरी, 2021 में जुड़े अतिरिक्त खातों की तुलना में मार्च, 2021 में खातों में बढ़ोतरी के संदर्भ में प्रमुख उद्योगों में लौह अयस्क खदानों, कूरियर सेवाओं, रेस्तरां, सड़क मोटर परिवहन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शोधन, लोहा और इस्पात उद्योग और कंप्यूटर निर्माण, विपणन व उपयोग से जुड़े प्रतिष्ठानों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। ■

प्रधानमंत्री का 'वेसक विश्वोत्सव' में मुख्य वक्तव्य

'कोविड-19 के बाद धरती अब पहले जैसी नहीं रहेगी'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 'वेसक विश्वोत्सव' को संबोधित किया। महासंघ के सदस्य, नेपाल और श्रीलंका के प्रधानमंत्री, मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह और श्री किरेन रिजिजू, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के महासचिव भंते डॉ. धम्मपिय भी इस आयोजन में उपस्थित थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वेसक दिवस भगवान बुद्ध को स्मरण करने का दिन है। हमें उनके आदर्शों और त्याग को याद करने का अवसर मिलता है, जो उन्होंने धरती को बेहतर बनाने के लिये किया।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष उन्होंने वेसक दिवस कार्यक्रम को उन सभी अग्रिम मोर्चे के योद्धाओं को समर्पित किया था, जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ मानवता को बचाने की जंग कर रहे थे। एक साल बाद भी कोविड-19 महामारी ने हमें छोड़ा नहीं है। भारत सहित तमाम देश महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जीवन में ऐसी महामारी कभी-कभार ही आती है, लेकिन यह अपने साथ त्रासदी और संत्रास लेकर आई है तथा हर देश के घर-घर को इसने पीड़ा दी है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी ने अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाला है और हमारा ग्रह कोविड-19 के बाद पहले जैसा नहीं रहेगा।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के बाद से कई उल्लेखनीय सुधार हुये हैं, जैसे महामारी को आज बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसके आधार पर हमारी रणनीति मजबूत हुई कि हम इससे लड़ सकें और हमने वैक्सीन भी तैयार की। वैक्सीन जीवन बचाने और महामारी को हराने के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन का विकास करने वाले वैज्ञानिकों की सराहना की, जिन्होंने साल भर में ही वैक्सीन बना दी। उन्होंने कहा इससे मनुष्य की दृढ़ता और उसके तप का पता चलता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध के जीवन के चार प्रकरण हैं, जिन्होंने मानव पीड़ा का उन्मूलन करने के लिये उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष तमाम लोग और संगठन मानव पीड़ा को दूर करने के लिये एक-साथ उठ खड़े हुये थे। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों और बौद्ध संगठनों ने उपकरणों और सामग्री का भरपूर योगदान किया था। श्री मोदी ने कहा कि ऐसा कर्म भगवान बुद्ध के उपदेश 'भवतु सब्ब मंगलम्' (सबके

लिये भलाई, करुणा और कल्याण) के अनुरूप है।

श्री मोदी ने कहा कोविड-19 से जंग करते समय हमें अन्य चुनौतियों से मुख नहीं मोड़ लेना चाहिये, जिनका सामना आज पूरी मानवता को करना पड़ रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन आदि। उन्होंने कहा कि मौजूदा पीढ़ी की लापरवाह जीवन-शैली ने भावी पीढ़ी को खतरे में डाल दिया है। हमें यह संकल्प करना होगा कि हम अपने ग्रह को चोट नहीं पहुंचायेंगे।

श्री मोदी ने भगवान बुद्ध का उल्लेख करते हुये कहा कि वे हमेशा उस जीवन-शैली पर जोर देते थे, जहां प्रकृति को माता समझना सर्वोपरि था। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पेरिस लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में भारत चंद बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत के लिये सम्यक जीवन केवल शब्द ही नहीं है, बल्कि कर्म भी है।

श्री मोदी ने कहा कि गौतम बुद्ध का जीवन शांति, सौहार्द और सह-अस्तित्व की शिक्षा देता है, लेकिन आज भी ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो नफरत, आंतक और पागल हिंसा पर फलती-फूलती हैं।

उन्होंने कहा ऐसी ताकतें उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर यकीन नहीं करतीं। लिहाजा, इस बात की जरूरत है कि उन लोगों का आह्वान किया जाये, जो मानवता में विश्वास करते हैं; वे साथ आयें तथा आतंकवाद और कट्टरपंथ को परास्त करें। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुध्द के उपदेश और सामाजिक न्याय का महत्व पूरे विश्व को जोड़ने वाली शक्ति बन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध पूरे ब्रह्माण्ड के लिये सद्बुद्धि का भंडार हैं। हम सब उनसे समय-समय पर ज्ञान का प्रकाश ले सकते हैं तथा करुणा, सार्वभौमिक दायित्व और कल्याण के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं।

श्री मोदी ने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया, "बुद्ध ने वाह्य आवरण को उपेक्षित करके सत्य और प्रेम की विजय पर विश्वास करने की शिक्षा दी।" इस सिलसिले में उन्होंने सबसे आग्रह किया कि वे भगवान बुद्ध के आदर्शों के प्रति कटिबद्धता दोहरायें।

श्री मोदी ने सबसे पहले विपदा का सामना करने वालों, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों, डॉक्टरों, नर्सों और स्वयंसेवियों को धन्यवाद दिया कि वे हर दिन दूसरों का जीवन बचाने के लिये खुद को जोखिम में डालते हैं। उन्होंने पीड़ितों और अपने प्रियजनों को खो देने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ■

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुएल मैक्रां के बीच टेलीफोन वार्ता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमेनुएल मैक्रां के साथ 26 मई को टेलीफोन पर बात की। श्री मोदी ने कोविड के खिलाफ भारत की कार्रवाई के सिलसिले में फ्रांस द्वारा दी गई सहायता के लिये राष्ट्रपति श्री मैक्रां को धन्यवाद दिया।

दोनों नेताओं ने पारस्परिक हितों से सम्बंधित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत भी की। उन्होंने हाल में सम्पन्न हुए भारत-यूरोपीय संघ नेतृत्व बैठक के सकारात्मक परिणामों पर संतोष व्यक्त किया।

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि संतुलित और समग्र मुक्त व्यापार तथा निवेश समझौतों पर बातचीत दोबारा शुरू की जाये। उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ संपर्कता साझेदारी को स्वागत-योग्य कदम बताया।

दोनों नेताओं ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि हाल के वर्षों के दौरान भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी और गहरी व शक्तिशाली हुई है। उन्होंने सहमति व्यक्त की कि दोनों देश पोस्ट-कोविड युग में मिलकर काम करते

रहेंगे। श्री मोदी एक बार फिर राष्ट्रपति श्री मैक्रां को भारत पधारने का न्योता दिया कि हालात सुधरते ही वे जल्द से जल्द भारत का दौरा करें। ■

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे त्शेरिंग के बीच टेलीफोन वार्ता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 मई को भूटान के प्रधानमंत्री डॉ. लोटे त्शेरिंग के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।

भूटान के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी की वर्तमान लहर से लड़ने में भारत और भारतवासियों के साथ एकजुटता दिखाई। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भूटान सरकार और भूटानवासियों को उनकी सद्भावनाओं और समर्थन के लिये धन्यवाद दिया।

उन्होंने भूटान नरेश के नेतृत्व में महामारी के खिलाफ जंग में भूटान की भूमिका की सराहना की और महामारी के खिलाफ किये जाने वाले प्रयासों के लिये लाइनछिन को शुभकामनायें दीं।

दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त कि मौजूदा संकट से भारत और भूटान के बीच विशेष मैत्री को और बढ़ावा दिया जा सकता

है। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बंध आपसी समझ, आपसी सम्मान, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोगों के बीच सौहार्द पर आधारित हैं। ■

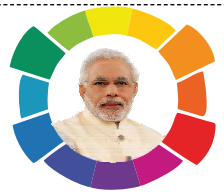

BECOME PART OF A VIBRANT IDEOLOGICAL MOVEMENT
BECOME PROUD MEMBER OF 'KAMAL SANDESH'

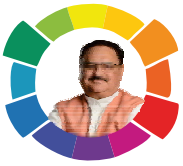

SUBSCRIPTION DETAILS

Name : .....

Address : .....

..... Pin : .....

Phone : ..... Mobile : (1)..... (2).....

E-mail : .....

SUBSCRIPTION TYPE						
	One Year	₹350/-	☐	Life Time (English or Hindi)	₹3000/-	☐
	Three Years	₹1000/-	☐	Life Time (English+Hindi)	₹5000/-	☐

(DETAIL OF THE PAYMENT)

Cheque/Draft No. :..... Date :..... Bank : .....

Note : * DD/Cheque will be made in favour of "**Kamal Sandesh**"
* Money order and Cash accepted with details

(Subscriber's Signature)

KAMAL SANDESH

SEND YOUR DD/CHEQUE ON THIS ADDRESS
Dr. Mookerji Smruti Nyas, PP-66, Subramania Bharati Marg, New Delhi-110003
Ph.: 011-23381428 **Fax:** 011-23387887 **E-mail:** kamalsandesh@yahoo.co.in

KAMAL SANDESH - DEDICATED TO NATIONAL CAUSE

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

गुजरात और दीव में चक्रवात तौकते से उत्पन्न स्थिति और क्षति का आकलन हेतु हवाई सर्वेक्षण करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी के डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के बारे में देशभर के राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh

@KamalSandesh

kamal.sandesh

KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

छायाकार: अजय कुमार सिंह